मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर चिंता

प्रिलिम्स के लिये:

नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

मेन्स के लिये:

वर्तमान परीक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ, नीतियों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

शिक्षा के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, परीक्षा प्रणाली अधिगम के परिणामों को आयाम देने और अकादमिक प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हालाँकि, बार-बार होने वाले घोटालों, असंगत मानकों और रटकर याद करने पर व्यापक फोकस ने भारत मेंमौजूदा परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

भारत में मौजूदा परीक्षा प्रणाली के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

विश्वसनीयता और शैक्षिक मानक:
परीक्षा सत्र के दौरान घोटाले परीक्षा बोर्डों की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं।
विश्वसनीयता की कमी शैक्षिक मानकों को प्रभावित करती है क्योंकि शिक्षण परीक्षा पैटर्न के साथ संरेखित होता है, जो प्रायः
रटने को बढ़ावा देता है।
अल्पकालिक स्मरण:
मध्यावधि, सेमेस्टर परीक्षा और यूनिट परीक्षण एक लघु कार्यक्रम प्रदान करते हैं लेकिन अल्पकालिक स्मरण पैटर्न को प्रोत्साहित करते हैं।
छात्र प्रायः अंकों के लिये अध्ययन करते हैं और परीक्षा के तुरंत बाद सीखी गई पाठ/विषय वस्तु को भूल जाते हैं।
शिक्षा को अल्पकालिक स्मरणीय बनाने के बदलेदीर्घकालिक अधिगम, आंतरिक ज्ञान के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक होना चाहिये, जिससे छात्रों की क्षमताओं का प्रभावी ढंग से परीक्षण किया जा सके।
मूल्यांकन गुणवत्ता:
संस्थानों में योगात्मक परीक्षा की वैधता और तुलनीयता आज अर्थहीन है। ऐसी शिकायतें हैं कि परीक्षा बोर्ड केवल स्मृति का परीक्षण करते हैं, जिसके कारण छात्रों को उच्च-स्तरीय सोच विकसित करने के बदलेउत्तर याद रखने के लिये प्रशिक्षित किया
जाता है।
इसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्रों में प्रायः भाषा की त्रुटियाँ, अप्रासंगिक प्रश्न और वैचारिकता में त्रुटियाँ जैसी गंभीर खामियाँ होती
हैं।
परीक्षा प्रणाली नकल और कदाचार से ग्रस्त है, जैसे– नकल करना, लीक करना, प्रतिरूपण करना आदि।
यह मूल्यांकन और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को कमज़ोर करता है।
विकेंद्रीकृत प्रणाली:
भारत में मूल्यांकन के विविध तरीकों के साथ कई उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणालियाँ हैं, जिनमें 1,100 विश्वविद्यालय, 50,000 संबद्ध कॉलेज और 700 स्वायत्त कॉलेज शामिल हैं।
कुल छात्र नामांकन 40.15 मिलियन से अधिक है, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये 60 स्कूल बोर्ड हैं, जो सालाना 15 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रामाणित करते हैं।

गोपनीयता और मानकीकरण को अच्छे परीक्षा बोर्डों की पहचान माना जाता है, लेकिनउचित जाँच के बिना गोपनीयता घोटालों को जन्म
देती है।
परीक्षाओं में एकरूपता, निरंतरता की मांग करते हुए, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में प्रयोग में बाधा बन सकती है।
इससे शिक्षा की विश्वसनीयता पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। एक गतिशील और प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लियेनवाचार की संभावना के साथ मानकीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।
रोज़गार क्षमता पर प्रभाव:
नियोक्ता उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिये संस्थागत प्रमाणपत्रों के बदले उनके मूल्यांकन पर भरोसा करते हैं।
उच्च स्तरीय शिक्षा पर ज़ोर रोज़गार के लिये महत्त्वपूर्ण है, फिर भी संस्थागत परीक्षाएँ प्रायः कम पड़ जाती हैं।
इसने बदले में प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल के लिये एक कोचिंग बाज़ार तैयार किया है।

परीक्षा प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

सीखने के परिणाम सुनिश्चित करना:
स्पष्ट बेंचमार्क प्रदान करने के लिये सीखने के परिणामों के न्यूनतम मानक निर्दिष्ट किया जाए।
पाठ्यक्रम डिज़ाइन, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन प्रणालियों में योगदान करने के लिये सभी विषयों के शिक्षाविदों को प्रोत्साहित किया
जाए।

विषय और कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन:
व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिये विषय-विशिष्ट और कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए।
यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ और स्कूल बोर्ड प्रमाण-पत्र वास्तव में छात्रों की अधिगम की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित किया जाए।
व्यापक और चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन का समर्थन किया जाए जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग कर
सकें।
शिक्षक की भागीदारी और छात्र की भागीदारी के साथ पूरे पाठ्यक्रम में निरंतर मूल्यांकन पर ज़ोर दिया जाए।
नियंत्रण और संतुलन लागू करके योगात्मक मूल्यांकन और मूल्यांकन को पारदर्शी बनाए जाएं।
विश्वसनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं:
विश्वसनीयता बढ़ाने, प्रश्नपत्रों और मूल्यांकन को मानकीकृत करने के लिये मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
केंद्रीकृत और वितरित मूल्यांकन प्रणालियों दोनों के लिये बाज़ार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर समाधानों का अन्वेषण किया जाए।
मूल्यांकन प्रणालियों का बाहरी ऑडिट:
विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन प्रणालियों का नियमित बाहरी ऑडिट किया जाए।
विश्वसनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के लिये बेंचमार्क सिद्धांत तथा मानक स्थापित किया जाए।
पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निरंतरता के आधार पर ग्रेड परीक्षा बोर्ड, ऑडिट रिपोर्ट में इन पहलुओं को दर्शाते हैं।
छात्रों के लिये पारदर्शिता उपाय:
पारदर्शिता के लिये उपाय लागू किया जाए, जिससे छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुँचने और शिकायतों का समाधान करने की अनुमति
मिले।

शिक्षा से संबंधित पहलें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
नई शिक्षा नीति 2020
सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न1. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का शिक्षा पर प्रभाव है? (वर्ष 2012)

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (D)

मेन्स

प्रश्न1. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/concerns-over-existing-examination-system